hon. Minister to have a sort of 'National Programme' and to see how this problem of rehabilitation is to be tackled and settled both for Bangla Desh evacuees and for old displaced persons and also for migrants whose figure is not less than 12 lakhs.

I would appeal to the hon. Minister and the Prime Minister to consider one thing. The Ministry of Labour and Employment is a very big department. They have so many complex problems to face and the rehabilitation problem has become more complex due to heavy influx of Bangla Desh evacuees So, there should be a separate Ministry to look after the interests of displaced persons, both old and new, and Bangla Desh evacuees. I would again appeal to the hon. Prime Minister to consider it.

17.34 hrs.

PROCLAMATION IN RELATION THE STATE OF WEST BENGAL

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. C. PANT) : I beg to lay on the Table—

(i) A copy of the Proclamation (Hindi and English versions) dated the 29th June, 1971, issued by the President under clause (1) of article 356 of the Constitution in relation to the State of West Bengal, published in Notification No. G. S. R. 984 in Gazette of India dated the 29th June, 1971, under article 356(3) of Constitution. [*Placed in Library. See* No. LT—554/71.]

(ii) A copy of the Order (Hindi and English versions) dated the 29th June, 1971, made by the President in pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of the above Proclamation, published in Notification No. G. S. R. 985 in Gazette of India dated the 29th June, 1971. [*Placed in Library. See* No. LT—554/71.]

(iii) A copy of the Report (Hindi and English versions) of the Governor of West Bengal dated the 28th June, 1971 to the President.

[*Placed in Library. See* No. LT—555/71.]

SHRI SAMAR MUKERJEE (Howrah) : Shame ! Because they are losing the majority, the President's Rule is imposed.

17.35 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

STATEMENT *RE.* APPOINTMENT OF A MINISTER WITHOUT PORTFOLIO TO DEAL WITH PROBLEMS OF WEST BENGAL

MR. SPEAKER : The hon. Prime Minister.

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF HOME AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI INDIRA GHNDHI) : Mr. Speaker Sir, as the House is aware, by a proclamation issued this morning, the President has taken over the administration of the State of West Bengal. The Central Government are anxious that all problems relating to West Bengal which are within their competence should be dealt with expeditiously. Very serious problems and an abnormal situation have been created in West Bengal and some other States by the massive influx of refugees in so short a period. These matters need to be given special attention and tackled urgently. It has, therefore, been decided to appoint a Minister of Cabinet rank as Minister, without portfolio with immediate effect. For the present, Shri Siddhartha Shankar Ray, Minister of Education, Social Welfare and Culture will be entrusted with this responsibility in addition to his existing duties. As soon as the consideration of the Demands for Grants of his Ministry is completed, he will look after this exclusively.

SHRI SAMAR GUHA (Contai) : The most urgent steps is to shift Mr. Dhavan from Bengal. Shanti Swarup Dhavan has created all kinds of 'Ashanti',

MR. SPEAKER : Nothing without my permission, please. Mr. Raja Ram Shastri.

17.37 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS, 1971-72—*Contd.*

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

श्री राजा राम शास्त्री (वाराणसी) : अध्यक्ष महोदय, मैं उन लोगों की तरफ सदन

[श्री राजा राम शास्त्री]

का ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो श्रम की सबसे निचली सीढ़ी पर हैं। मेरा मतलब ऐसे श्रमिकों से है, जिन को इस-आर्गनाइज्ड लेबर कहा जाता है, जो किसी संगठन में नहीं आते हैं, जैसे रेलवे के कुली या इस तरह के अन्य श्रमिक, जो ठेकेदारों के मातहत रहते हैं। वे किसी कानून से संचालित नहीं होते हैं और उनके लिए कोई प्रबन्ध नहीं होता है। अगर उन की कोई दिक्कतें होती हैं और वे सरकार से शिकायत करते हैं, तो यह कहा जाता है कि आप सरकार के नौकर नहीं हैं, इसलिए सरकारी कानून आप पर लागू नहीं होते हैं।

जो सरकारी कानून हैं, वे ठेकेदार पर लागू होते हैं, क्योंकि ठेकेदार सरकार से ठेका लेता है, जबकि मजदूर लोग सीधे सरकार के मुलाजिम नहीं होते हैं। अगर ठेकेदार से कहा जाये कि अन्य श्रमिकों को जो सुविधायें मिली हुई है, तुम अपने मजदूरों को भी वे सब सहूलियतें पहुंचाओ, तो उस के लिए भी कोई कानून नहीं है। ठेकेदार कहता है कि मेरा और मजदूरों का सीधा सम्बन्ध है, सीधा कन्ट्रेक्ट है ; जिन शर्तों पर मैं चाहता हूं, उन पर उनको रखता हूं और अगर वे उन शर्तों पर राजी हैं, तो कोई जरूरत नहीं है कि मैं उन को और सहूलियतें दूं—और अगर मैं उन को और सहूलियतें देता हूं, तो मुझे फायदा नहीं पहुंचता है, सरकार को ठेकेदारी का जो पैसा मुझे देना पड़ता है, वह लाभप्रद नहीं रहता है। इस तरह वे बेचारे उन सहूलियतें से वंचित रह जाते हैं।

सरकार को उन लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए और कानून में कुछ ऐसा इन्तजाम होना चाहिए कि अगर ठेकेदारी प्रथा रहती भी है—होना तो यह चाहिए कि वे लोग सरकार के नौकर और कर्मचारी माने जायें, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता है और ठेकेदारी प्रथा कायम रहती है—, तो ठेकेदार को वे सब सहूलियतें अपने मजदूरों को देनी पड़ेंगी, जो सहूलियतें कि सरकारी इंतजाम के अन्दर या जो आर्गनाइज्ड लेबर है कारखानों के अन्दर चाहे वह प्राइवेट सैक्टर में हो, चाहे पब्लिक सैक्टर में हो उन को मिलती हैं वह सहूलियतें ठेकेदारों को देनी पड़ेंगी। अगर वह नहीं देते हैं तो उन की ठेकेदारी खत्म होती है। यह एक बहुत न्याय की बात है। इस तरह से एक बड़ी तादाद हमारे मजदूरों की है जिन का कि कोई पुरसां हाल नहीं है। न वह इधर के होते हैं न उधर के होते है। सिर्फ कानूनी दिक्कतों की वजह से या कुछ सहूलियतें न होने की वजह से उन्हें यह दिक्कत हो रही है और उन का कोई पुरसां हाल नहीं है। यह बात बहुत गलत मालूम होती है खास कर के एक ऐसी सरकार के लिए, एक ऐसे देश के लिए जिस ने कि समाजवाद का उद्देश्य अपने सामने रखा है।

इसी तरीके से श्रीमन्, मैं खेत मजदूरों की तरफ भी आप का ध्यान आकृष्ट करूंगा। उन के संबंध में भी कानूनी दिक्कते है। कहा जाता है कि वह मजदूर है ही नहीं। वह कृषि विभाग के अन्दर आते हैं, कृषि मंत्रालय के अन्दर आते हैं, कृषकों से उन का सम्बन्ध है और वह मजदूर नहीं हैं। वह कारखाने के मजदूर नहीं है, औद्योगिक मजदूर नहीं हैं। इसलिए उन के ऊपर कोई भी चीज लागू नहीं होती। वह भी एक अजीब बात है। इतनी बड़ी तादाद खेत मजदूरों की जो कि शायद हमारी अर्थ-व्यवस्था में सबसे निचली सीढ़ी पर है, सब से अधिक उन की दिक्कतें हैं, सामाजिक रीति से और आर्थिक रीति से हर प्रकार से वह गए गुजरे हैं लेकिन सिर्फ कानूनी दिक्कतों से, कानूनी बहाने बना कर हम उनको हर प्रकार की सुविधा से वंचित रखते हैं और एक ऐसे वर्ग को जो कि बराबर ही असंतुष्ट रहता है और बराबर ही वंचित रहता हैं उस को हम लोग अपनी अर्थ-व्यवस्था में बनाए हुए हैं। मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि उन की तरफ ध्यान दिया जाय। लेबर कमीशन ने इस पर विचार किया था लेकिन लेबर कमीशन के जो टर्म्स आफ रेफरेंस थे उस के अन्दर वह चीज नहीं आई। इसलिए कि वह औद्योगिक मजदूरों से सम्बन्ध रखता था और लेबर कमीशन मजबूर था इस बात के लिए कि वह खेत मजदूरों

की तरफ ध्यान न दे हालांकि उस से कुछ तकलीफ उस मामले में भी और उसका कुछ पता लगाया। लेकिन उस से कुछ काम चलने वाला नहीं था। कोई सिफारिश वह उन के सम्बन्ध में नहीं कर सकता था और न उस से किया। मैं यह चाहता हूं कि होना यह चाहिए कि उनकी तरफ खास तौर से ध्यान दिया जाय। विशेष रूप से मैं इसलिए कहूंगा कि वह न केवल आर्थिक रूप से गिरे हुए हैं बल्कि सामाजिक रूप से भी गिरे हुए हैं। आप जानते हैं कि खेत मजदूर ज्यादातर हरिजन वगैरह होते हैं जो कि सामाजिक सीढ़ी में भी सब से निचली सीढ़ी पर हैं। तो यह एक दोहरे तरीके से जो गिरे हुए हैं आर्थिक तरीके से और सामाजिक तरीके से उन के ऊपर कोई कमीशन काम न करे, उन को न मजदूर माना जाय न किसान माना जाय, क्योंकि किसान तो वह हैं नहीं, किसान तो तब होंगे जब आप उन को जमीन देंगे, जमीन आप के पास है नहीं न आप दे सकते है, ऐसी हालत में सिवाय इस के कि मजदूरों की सुविधायें उन को दी जायं और कोई रास्ता रहता नहीं है उन के उद्धार का। उन की हालत क्या है कि उन के पास बारगेनिंग पावर भी नहीं है। उन को लोग सताते हैं, मारते है, पीटते हैं। दूसरे मजदूर शहरों के जो होते है कोई आदमी उन से मजदूरी का ठेका करता है कि इतनी मजदूरी देंगे, इतना हमारा काम करो, अगर वह मजदूरी नहीं करना चाहते तो वह वहां से चले जाते हैं। कहते हैं कि मैं मजदूरी नहीं करूंगा, आप अपने घर जाइए। लेकिन खेत मजदूर भी क्या ऐसी बात कर सकता है? खेत मजदूर अगर ऐसी बात कहता है तो उसके सामने यह सवाल आता है कि अच्छा, तुम निकलोगे किधर से? तुम जाओगे किस के खेत से होकर? तुम्हारी जायदाद लूट ली जायगी, तुम्हारा घर लूट लिया जायगा, तुम्हारी बेइज्जती कर दी जायगी। तो एक जो स्वतंत्र मजदूर के अन्दर बारगेनिंग पावर होती है कि एक जगह से खड़ा होकर वह यह कह सकता है कि मैं यह काम मानता हूं, यह नहीं मानता हूं, यह स्वतंत्रता भी उस को नहीं है। ऐसे लोगों के लिए कानून में जरूर गुंजाइश होनी चाहिए, कम से कम औद्योगिक मजदूरों को जो लाभ होते हैं, जो सुविधायें प्राप्त हैं, हमारे कानून में वे उन को भी प्राप्त हों। इस सम्बन्ध में आप कुछ करें—कोई कमीशन बैठायें या किसी कानून की शक्ल में उस को लायें, जिससे कि समाज के एक बहुत बड़े तबके का ऐसा तबका जो वंचित है, शोषित है; पददलित है, उस का किसी तरह से उद्धार हो, वरना यह कहने का कोई अर्थ नहीं होता कि हम लोग समाजवाद की ओर कदम उठा रहे हैं।

इसी प्रकार, श्रीमन्, एक और समस्या नेशनल-मिनिमम की है। लेबर कमीशन ने इस पर भी विचार किया था और वह इस नतीजे पर पहुंची कि हमारी अर्थ-व्यवस्था में यह सम्भव नहीं है कि हम कोई एक राष्ट्रीय न्यूनतम आय मकर्रिर कर सकें। यह भी विचार हुआ था कि क्या इस को इण्डस्ट्रीज-वाइज या रिजन-वाइज किसी किसी क्षेत्र में लागू किया जा सकता है, जहां पर इस बात की सम्भावना हो इतनी इन्कम हो, इतनी गुंजाइश हो कि किसी उद्योग में मजदूरों को, एक न्यूनतम मजदूरी दी जा सके, किसी क्षेत्र में जो खुशहाल क्षेत्र हो वहां पर कुछ ऐसा किया जाय। लेकिन वह भी एक सुझाव ही था और उस पर भी कुछ नहीं हुआ। यह एक बड़ी हैरत की बात हैं, एक बड़े अफसोस की बात है कि एक समाजवादी व्यवस्था में इस बात पर ध्यान न दिया जाय और लोगों को इस बात का कोई इतमिनान न हो कि उनकी जिन्दगी कल कायम रहेगी या नहीं रहेगी, उन के पास कोई काम रहेगा या नहीं रहेगा। अगर कोई काम रहता भी है, कोई काम करता भी है तो उन को इतना पैसा मिलेगा जिस में वह अपनी जिन्दगी का निर्वाह कर सकें, दूसरे दिन उन का स्वास्थ्य इस लायक रह सके कि वे काम कर सकें—इस बात का भी इतमिनान उन को नहीं है। इस बात का आश्वासन भी हमारी समाजवादी व्यवस्था में नहीं है—यह एक अजीब बात है और मैं समझता हूं कि इस पर ध्यान देना चाहिए और जल्दी से हम को इस बात का इन्तजाम करना चाहिए कि हम कोई न्यूनतम आय

[श्री राजा राम शास्त्री]

ऐसे लोगों के लिए मुकर्रिर करें जो कि हमारी अर्थ-व्यवस्था और हमारी समाजवादी व्यवस्था के सब से पिछड़े हुए लोग हैं।

इन शब्दों के साथ, श्रीमन, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*SHRI THA KIRUTTINAN (Sivaganja) : Mr. Speaker, Sir, the Demands for Grants of the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation are before this House and I am happy to participate in the discussion on behalf of Dravida Munnetra Kazhagam.

Sir, at the outset, I would refer to the Report of the National Labour Commission recently submitted to the Government. I regret very much to point out that the Government have not yet given due consideration to the recommendations of the Labour Commission and have not initiated any steps for implementing even very important recommendations. For instance, the Commission has recommended the setting up of Industrial Relations Council as the first step for ensuring industrial peace in the country. So far this recommendation has not seen the light of the day. I request the hon. Minister of Labour to give effect to this recommendation by immediately setting up the Industrial Relations Council.

The Labour Commission has also suggested amendment of Section 2(a) of Industrial Disputes Act. The State Governments are not now empowered to intervene and settle the disputes that arise in the central industrial undertakings which are located in various States. The maintenance of law and order is the sole responsibility of the State Government. I may point out here that frequent industrial disputes in the central public undertakings lead to serious law and order situation in the States. However, as the State Governments are not clothed with the authority to intervene and settle such disputes, they have to rest content by remaining mute witnesses and silent spectators of worsening law and order problem. Keeping this in view, the Labour Commission has suggested the amendment of Section 2(a) of Industrial Disputes Act, enabling the State Governments to effectively intervene at the appropriate moment and prevent explosion of industrial unrest. I request the Government to come forward at the earliest with the necessary amendment to the Industrial Disputes Act.

At the moment, Sir, the Railways do not come within the purview of Industrial Disputes Act because the Railways are not unfortunately treated as an industry. It is high time that the Railways are treated as an industry and brought under the operational scope of Industrial Disputes Act.

The Tamil Nadu Chief Minister, Kalaignar Karunanidhi, has made a valuable suggestion regarding extension of gratuity scheme to cover all the industrial workers throughout the country. I am sure that the hon Minister of Labour will not hesitate to accept this worthwhile suggestion and extend the benefit of gratuity scheme to all the industrial workers.

I would take this opportunity to point out that it is very necessary to constitute a Labour Welfare Board in each State, through which alone many meaningful labour welfare programmes can be undertaken. I am happy to state that the Tamil Nadu Government have allocated a sum of Rs. 5 crores to the State Labour Welfare Board. Considering the magnitude of the welfare activities to be undertaken, you will appreciate that this amount is quite inadequate. I would suggest that the Central Government should sanction a matching grant—it may be Rs. 5 crores or Rs. 10 crores—to the State Governments so that the State Labour Welfare Fund gets swelled and the State Governments are enabled to implement purposeful labour welfare programmes.

The Employees State Insurance Scheme started in 1955 has not been functioning as it should and in consequence the Tamil Nadu Government have been greatly handicapped. An unfortunate feature of this scheme is that the workers who are members of this Scheme get the benefits under this scheme, while their families are left to fend for themselves. This

*The original speech was delivered in Tamil.

anomaly should be rectified so that the families of workers are also covered. In 1967-68 the labour contributed a sum of Rs 12.44 crores to the E.S.I. fund, while the employers' share of contribution was Rs. 13 64 crores. You will no doubt agree with me, Sir, that the employers' contribution is woefully inadequate.

In a meeting of the E.S.I.C. held on 17-9-1969 a resolution was adopted restricting the per-head expenditure under this scheme to Rs. 50 and any amount in excess of this limit was to be borne by the respective State Governments. In Tamil Nadu, the Government are spending a sum of Rs. 61 per worker under this scheme, on account of which the State Government have to bear an additional burden of Rs. 75 lakhs. I am at a loss to appreciate how far it is just and proper for the E.S.I.C to put a ceiling of Rs. 50 per head. I would appeal to the good sense of the hon Minister of Labour and request him to get this Resolution of the E.S.I.C. immediately revoked.

The Tamil Nadu Government have in their eagerness to implement labour welfare programmes undertaken quite a number of works in hand But, to our dismay and horror, the E S I C. has put its foot down and directed the State Government not to proceed further. Many construction works stand paralysed. The hon. Minister of Labour should put an end to this sordid state of affairs.

The Committee under the chairmanship of Thiru Pattabhiraman, constituted in 1966, was critical about the sluggish manner in which the State Governments were reacting in the matter of implementing this Scheme. The Committee pointed out that the State Governments were not coming forward quickly for acquiring lands required for implementing labour welfare activities. The Tamil Nadu Government spontaneously took upon themselves the responsibility, purchased land and started construction of hospitals and dispensaries under the E.S.I. scheme. When the State Government is genuinely interested in implementing labour welfare programmes, it is highly improper for the E.S.I.C. to put some imaginary and arbitrary ceiling on expenditure, which is utterly unrelated to the dimensions of the problem.

Mr. Speaker, Sir, there was recently a Conference of Trade Unions and Management convened by the hon. Minister of Labour. The proceedings and the conclusions of this Conference, I request, should be placed on the Table of the House for the information of honourable Members.

The Railway Employees Progressive Union, of which I happen to be the President, has on its rolls thousands of employees. I am sorry to state that this Union has not yet been recognised by the Railway Administration. I request the Minister of Labour to use his good offices for according recognition to the Railway Employees Progressive Union.

While the labour in the industrial sector are assured of fixed minimum wages and also pensionary benefits, the landless agriculture labour have no hope of getting regular minimum wages for their sustenance. I would request the hon. Minister of Labour to think of ways and means to alleviate the sufferings of landless agriculture labour and to assure them compulsory minimum wages. I would also suggest that instead of giving cash incentives alone, the Government should undertake a massive housing programme for the labour.

Much has been bruited about the unemployment problem in our country, and the imperative necessity of creating ample employment opportunities. The Government have allocated a sum of Rs. 50 crores for a crash programme. But I am pessimistic about the success of this crash programme. This crash programme is confined to the uneducated unemployed. I am of the view that initially the problem of educated unemployed must be solved on a war footing.

Finally, I would refer to the question of rehabilitation of refugees coming from Burma and Ceylon. The Tamil Nadu Government have undertaken several schemes for their rehabilitation. As the influx of refugees is in lakhs, the Central Government should be liberal in extending financial assistance to the State Government for tackling this stupendous and gigantic problem.

With these few words, I conclude.